

ग्रसाचारण

### EXTRAORDINARY

भाग 1 -- सम्बद्ध 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

मं॰ 96]

नई विल्ली, बृहस्पतिबार, मई 28, 1970/ ज्येड्ड 7, 1892

No. 96]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 1970/JYAISTHA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पूच्छ संश्या की जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में एका जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

# MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 27th May, 1970

No. 5(17)/70-A. E. Ind. (I).—Since about 1957 Government had been exercising informal control over the prices of the three passenger cars namely, Ambassador, Fiat and Standard and the manufacturers of these three cars accepted that control. In May, 1966, in response to requests by these manufacturers for price increases, Government requested the Tariff Commission, under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951, to undertake an enquiry into, inter alia, the cost structure and the fair selling prices of these three passenger cars and to make suitable recommendations in that behalf. While the recommendations of the Tariff Commission were under examination, one of the three manufacturers of passenger cars increased the price of their car by a substantial amount and another gave notice of their intention to do so. To meet this situation and to ensure availability of passenger cars at fair prices, Government, after consideration of the recommendations of the Tariff Commission and taking into account the relevant factors subsequent to the receipt of the said recommendations, determined the fair prices at which the said three passenger cars should be bought and sold and notified such prices by an Order under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 on 21st September 1969. This Order was challenged by inter alia, the said three car manufacturers in Writ Petitions before the Supreme

Court. The Supreme Court, after hearing the Writ Petitions for several days, recommended to Government on the 6th May, 1970 as follows:--

- 2. In pursuance of the recommendations of the Supreme Court, Government have decided to appoint a Commission for the purpose of recommending fair selling prices for the said three passenger cars, namely, Ambassador, Fiat and Standard. The Commission will consist of the following:—
  - Justice Sarjoo Prasad Singh, Retired Judge of the Patna High Court— Chairman.
  - (ii) Shri R. K. Khanna, Chartered Accountant-Member.
  - (iii) Brig. V. Minas, Director of Inspection (Vehicle) Department of Defence Production—Member.

Shri R. K. Tikku, Deputy Secretary. Department of Industrial Development will function as the Secretary of the Commission.

- 3. In recommending fair selling prices of cars, the Commission will take into account all matters relevant to the determination of fair prices.
- 4. The Commission will be at liberty to obtain the assistance of other persons including experts in Cost Accounting.
  - 5. The Commission will be entitled to lay down its own procedure.
- 6. The Commission will submit its Report within four months from the date of its constitution.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. V. SUBRAHMANIAN, Jt. Secy-

# श्रोद्योगिक विकास, श्रान्तरिक व्यापार तथा समबायकार्य मंत्रासय

(श्रोद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 मई, 1970

संख्या 5(17)/7 - ए०ई० बाई० (1).—1957 के सरकार एम्बसेडर, फियेट तथा स्टेंडर्ड तीनों सवारी गाड़ियों के मूल्य पर अनीपचारिक नियंत्रण करती रही है और इन कारों के उत्पादकों ने उस नियंत्रण को माना है। मई, 1966 में इन उत्पादकों के अनुरोध पर सरकार ने प्रणस्क आयोग अधिनियम, 1951, के खण्ड 12(घ) के अन्तर्गत प्रशुल्क आयोग को अन्य वस्तुओं के साथ-साथ इन तीनों कारों की लागत ढांचे की जांच करने तथा इन कारों के उचित विकय मूल्य के बारे में समचित सफारिशें करने के फिए निवेदन किया था। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन ही थीं कि

इन उत्पादकों में से एक ने अपनी कार के विक्रय मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर दी और दूसरे ने सरकार को ऐसा करने के अपने इरादे से सूचित किया। इस परिस्थित का सामना करने के लिए कारों की समुचित विक्रय मूल्य पर उपलब्धि को सुनिष्चत करने की दृष्टि से सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पण्चात् तथा इन मिफारिशों के प्राप्त होने के बाद के संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य का निर्धारण किया जिस पर उक्त तीनों सवारी कारों खरीदी या बेची जानी चाहिए। इन मल्यों को 21 सितम्बर, 1969 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के खण्ड 18(छ) के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा श्रिक्षित्वित किया गया। इस आदेश को उक्त तीनों कार निर्माताओं द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतम न्यागालय में प्रस्तुत की गई याचिका में चुनौती टी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कई दिनों तक याचिका की सुनवाई करने के पश्चात् 6 मई, 1970 को सरकार से निम्नलिखित सिफारिश की थी:—

- "हम सरकार से सिफारिण करते हैं कि तीनों ही प्रकार की कारों अर्थात् फिएट, एम्बेसेडर तथा स्टेंडर्ड हं सास्ड के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रायोग नियुक्त किया जाय। हम सिफारिश करते हैं कि इस प्रायोग का प्रध्यक्ष एक न्यायाधीश हो, जो उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवामुक्त न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हो तथा श्रायोग में दो अन्य सदस्य हों—जिनमें से एक चार्टंड एकाऊन्टेंट तथा दूसरा आटोमोबाइस इंजीनियर हो। श्रायोग लागत लेखाकार विशेषक सिह्न किन्हों भी अन्य व्यक्तियों की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगा। भ्रायोग के गठन की तारीख से चार मास के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आयोग को उचित मल्य निर्धारित करने में संबंधित सभी संबद्ध मामलों पर विचार करने का अधिकार होगा—श्रायोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करने का हक होगा"।
- 2. उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने उक्त तीनों यात्री कारों—— श्रयात् एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टेंग्डं—के लिए उचित विश्वय मूल्यों की सिफारिण करने के प्रयोजन से एक आयोग की नियम्ति करने का निश्चय किया है। श्रायोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे—-
- ा. न्यायाधीश सर्जू प्रसाद सिंह, ग्रवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उ+च-त्यायालय प्रध्यक्ष
- 2. श्री भ्रार् के बाजा, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट सदस्य
- 3. ब्रिगे॰ वी॰ मिनास, निरीक्षण निदेशक (मोटर गाड़ी), रक्षा उत्पादन विभाग सदस्य

श्री<mark>शोगिक विकास वि</mark>भाग के उप-सचि<mark>ष श्री श्रा</mark>र० के० टिक्कू इस श्रायोग के सचिव के रूप में कार्य करेगे ।

- 3. श्रायोग, कारों के उचित बिकी मूल्य की सिफारिश करने के लिए उचित पुल्य निर्धारित करने से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगा ।
- अप्रयोग को, लागत ने ब्रा-विशेषज्ञ समेत अन्य स्यक्तियों से महायता प्राप्त करने के किए प्रति स्वतंत्रता होगी।
  - प्रायोग स्वयं भ्रपनी कार्य-विधि तैयार करने में मनदे होगा :
  - 6. श्रायोग, गठन की तारोख से चार मास को श्रवधि के अन्दर ही श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तृत करगा ।

# ब्रादेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए।

न्नार० वी० सुब्रह्मनियन, सं<mark>युक्त सचिव ।</mark>